प्रजनन अनुसंधान तथा उत्पादन के निम्नलिखित कार्यक्रम हैं:—

1. हरियाणा तथा आंध्र प्रदेश में क्रमशः हरियाणा तथा अंगोले जैसे संयुक्त गोपशु पशुयुध का उपयोग करके स्वदेशी नस्ल की संतति परीक्षण।

2. पी०ए०यू०, लुधियाना बी०ए०आई०एफ०, पुणे तथा के०ए०यू०, त्रिचुर में किसानों के पशुओं का उपयोग करते हुए वर्ण संकर सांडों का क्षेत्र संतति परीक्षण।

3. अन्य स्वदेशी नस्लों पर अर्थात अपने प्रजनन भू-भागों में वेचुर, पंगनूर तथा कंज्ञम के मूल्यांकन, लक्षण वर्णन तथा सुधार के कार्यक्रम प्रगति पर हैं। इसके अलावा पशुओं पर करन "खिस" करन "फ्राइज" तथा "फ्रिसवाल" में सिरे परीक्षण का अनुसंधान कार्यक्रम क्रमशः राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान करनाल तथा गोपशु परियोजना निदेशालय में प्रगति पर है।

जहां तक भैंस प्रजनन अनुसंधान का प्रश्न है, मुर्रा तथा सुर्ती नस्लों के संतति परीक्षण पर कार्य आरम्भ किया गया है। इन परियोजनाओं से सांडों तथा जांच किए गए सांडों (स्वदेशी, वर्ण-संकर तथा भैंस) का वीर्य सुधार कार्यक्रमों के लिए किसानों के साथ-साथ विभिन्न एजेंसियों को उपलब्ध कराया जा रहा है।

पशुपालन कार्यक्रम एवं योजना के संबंध में शिकायत

1978. **श्री नागमणि:** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को छोटा नागपुर में पशुपालन कार्यक्रम एवं योजना के संबंध में कोई शिकायत प्राप्त हुई है;

(ख) यदि हां, तो यह शिकायत किस प्रकार की है;

(ग) क्या केन्द्रीय सरकार को संबंधित राज्य सरकार से इस संबंध में कोई प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है;

(घ) यदि हां, तो उस प्रतिवेदन का ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इस संबंध में विलम्ब के क्या कारण हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अरविंद नेताम): (क) और (ख) जी हां, भारत सरकार द्वारा बिहार राज्य सरकार को 1990 से मार्च 1992 की अवधि के दौरान आवंटित 46.50 करोड़ रुपए की राशि के कथित कुप्रबंध के बारे में शिकायतें प्राप्त हुई हैं। बिहार के छोटानागपुर तथा संथाल परगना के लोगों के कल्याण के लिए सुअर, भैंस, गाय/बछड़े, भेड़ बकरी, कुक्कुट तथा पशुधन चारा/आहार और औषधि आदि के मुफ्त वितरण के उद्देश्य से इन निधियों का आवंटन जिला ग्रामीण विकास एजेंसी, जनजातीय विकास एजेंसी, विशेष घटक योजना, सामाजिक कल्याण तथा सामाजिक संगठनों को किया गया बताया गया है। कथित भ्रष्ट अधिकारियों द्वारा सेवाओं में तैनाती, स्थानान्तरण, नियुक्तियां तथा विस्तार अनियमितताओं के उदाहरणों का भी उल्लेख किया गया है।

चूंकि शिकायत में उठाए गए मामले बिहार राज्य सरकार के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आते हैं तथा केन्द्रीय कृषि मंत्रालय, पशुपालन विभाग का इन मुद्दों से सीधा कोई संबंध नहीं है, अतः इन शिकायतों को उचित जांच-पड़ताल तथा तत्काल कार्रवाई के लिए बिहार सरकार को भेज दिया गया था।

(ग) से (ङ) सातवीं योजना से 1994-95 तक केन्द्रीय कृषि मंत्रालय के पशुपालन एवं डेयरी विभाग द्वारा विभिन्न केन्द्र प्रवर्तित योजनाओं के अंतर्गत आवंटित निधियों के उपयोग के बारे में राज्य पशुपालन विभाग ने एक रिपोर्ट भेजी है। रिपोर्ट में यह प्रमाणित किया गया है कि आवंटित निधियों का पूरा-पूरा उपयोग किया गया है तथा बिहार के छोटानागपुर में निधियों का किसी प्रकार का कोई कुप्रबंध नहीं हुआ है।

Linking of Steel outlets of SAIL by Computer Network

1979. SHRI K.M. KHAN: Will the Minister of STEEL be pleased to state:

(a) whether the steel outlets, plants and offices of Steel Authority of India Limited across the country are to be linked by a computer network;

(b) if so, the details with background thereof;

(c) whether certain outlets, plants and offices have been identified for the purpose;

(d) if so, the names of each location-wise and if not, the reasons therefor;

(e) whether consumers of steel are also to be benefited with such facility; and

(f) if so, the details and if not, the reasons therefore?